मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- चंडीगढ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह की बजाय मंगलसेन ? 3
- ओबमाओं की अगवानी : यह गर्व की नहीं शर्म की बात है 4
- मोदी की सत्ता का फ्लिहाल कोई विकल्प नहीं 5
- डीयर मिस्टर केजरीवाल जी 5
- कृष्णपाल की सत्ता में अवतार की सेंधमारी 8
- डबुआ मंडी: घरों के आगे दीवार नहीं सड़क बनेगी 8

वर्ष 29 अंक 4 फरीदाबाद, शुक्रवार, 1-15 जनवरी 2016 फोन : - 9999595632 2 ₹

भ्रष्टाचारियो! तुम्हारे लिये प्रदूषण बढ़ना ही जरूरी

सम-विषम को बनाया तोड़ः केजरी की तुगलकी होड़

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार को एक नया प्रदूषण हाईवे आनन-फ़ानन में तैयार कर दिया है। एक जनवरी से कारों पर लागू होने वाली सम-विषम योजना पुलिस, ट्रांसपोर्ट व अन्य सम्बन्धित सरकारी अमले को कारचालकों की जेबें काटने का खुला परमिट ही है। दिल्ली में दर्ज 80 लाख गाड़ियों में से महज़ 10 लाख निजी कारें हैं। दूसरे शब्दों में यदि यह योजना पूरी तरह लागू कर दी गयी तो भी प्रदूषण ज्यों का त्यों रहेगा और सड़कों पर जम कर अफ़रा-तफ़री बढ़ेगी वह अलग से। लगता है मोदी को हराने के बाद अब केजरी के निशाने पर दिल्ली का मध्ययुगीन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है। कहते हैं तुगलक ने अपनी ज़िद में राजधानी दिल्ली से हज़ारों मील दूर दौलताबाद ले जाने में आधी आबादी मरवा दी और बाकी आधी वापस दिल्ली लाने में। केजरीवाल भी क्या यही दोहरायेंगे ? यदि डीज़ल कारें ही प्रदूषण का मुख्य स्रोत हैं तो क्या सबसे आसान हल यह नहीं होता कि केवल पेट्रोल कारें ही बनाई जायें ? ज़ाहिर है कार लॉबी केजरीवाल और मोदी को यह नहीं करने देगी।

मज़दूर मोर्चा, दिल्ली ब्यूरो

भारत देश महान् में और कुछ हो न हो पर एक खूबी तो जरूर है कि लगभग हर समस्या से कोई न कोई मुनाफ़ा कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढता है। बिजली संकट ने जनरेटर तथा इन्वर्टर उद्योग को बढाया तो जल प्रदूषण ने 'शुद्ध' पेयजल का बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। ठीक इसी तर्ज पर ज़्यों-ज़्यों देश में वायू प्रदूषण का स्तर बढता जा रहा है लूट-कमाई का करोबार तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है।

यदि देश में प्रदूषण न बढता तो एनजीटी (राष्ट्रीय ग्रीन ट्रब्यूनल) की स्थापना कैसे होती। और नहीं होती तो स्वतंत्र कुमार को सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृति के बाद कहीं और नौकरी खोजनी पड़ती। नब्बे के दशक में सर्वोच्च न्यायालय में तत्कालीन न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में एम.सी. मेहता का पीआईएल (जनहित याचिका) का धंधा कैसे फ़लता फूलता ? इन्हीं दोनों महानुभावों की जनहित याचिकाओं की बदौलत 20 वर्ष पूर्व दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 90 करोड़ के प्रदूषण जांच यन्त्र तथा विशेष वाहन खरीदे थे। इनका कभी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। सम्बन्धित यन्त्र निर्माता कम्पनी से सामान खरीद कर बुराड़ी स्थित जंकयार्ड में डाल दिया गया। कम्पनी का ना बिकने वाला माल बिक गया एम सी मेहता जी का मोटा कमीशन पक्का हो गया।

अगले दौर में वाहनों की प्रदूषण जांच के नाम पर धंधा चलाने के लाइसेंस जारी होने लगे। एक नकली सी मशीन लेकर बैठ जाओ। कुछ करने की जरूरत नहीं बस खाली 'धूमा पर्ची' काटे जाओ, बल्कि काट-काट कर वाहन मालिकों के घर पहुंचाते रहो ताकि वाहनों की दिहाड़ी न मारी जाय। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो दिल्ली के बाहर से वाहन गुजारने के लिये के एम पी व के जी पी जैसे बाइपास बनाने का धंधा सामने आया। गत 16 वर्षों से यह नाटक चल रहा है। राजनेताओं, भ्रष्ट अफ़सरों व उनके लगुओं-भगुओं ने इन बाइपास मार्गों के नक्शे देख कर आसपास की ज़मीनों में भारी निवेश कर दिया। इन मार्गों के निर्माण का सारा खर्चा निजी कम्पनियां उठायेंगी जिसके बदले

जस्टिस मार्कण्डेय काटजू

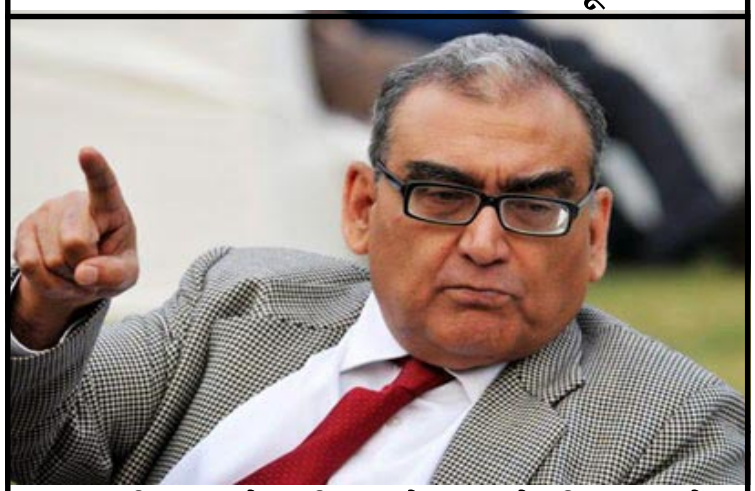

सम-विषम से पुलिस के अच्छे दिन आये

उन्हे लाइसेंस मिलेगा कि जनता का खून आयुपर्यन्त निचोड़ते रहें।

प्रदूषण के बढते जाने से लगभग सभी राज्यों में अब प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड स्थापित हो गये हैं। इनका चेयरमैन लगने की बोली करोड़ों से अरबों तक पहुंच गयी। लूट की रकम वसूलने के लिये ज़िला स्तर पर कार्यालय खुल गये, बड़े-बड़े अधिकारी व स्टाफ़ नियुक्त हो गये। सर्वविदित है कि किसी भी बोर्ड एवं इसके अधिकारियों की प्रदूषण नियन्त्रण में कतई कोई रूचि नहीं है। सब का एक सूत्री लक्ष्य वसूली एवं लूट-कमाई है। कुल मिलाकर इनका अर्थ यह हो गया है कि इन्हें पैसा देकर प्रदूषण बढाते रहो। इसी तर्ज पर अब दिल्ली में बड़े वाहनों को प्रदूषण फ़ैलाने की छूट के लिये 1400 से 2600 रुपये तक प्रवेश शुल्क देने होंगे। इन रुपयों को यदि कोई बचाना चाहे तो वह दिल्ली में घुसे बिना दो से तीन गुणा डीज़ल फूंक कर यानी दो से तीन गुणा प्रदूषण दिल्ली से बाहर फ़ैला कर अपने रास्ते जा सकता है।

देश भर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के नाम पर अरबों-खरबों रूपया डकारा जा चुका है। लेकिन नदियों का जल प्रदूषण बढता ही जा रहा है। यदि जल प्रदूषण न बढे, गंगा यमुना जैसी बड़ी नदियां गंदे नालों का रूप न धारण कर लें तो इन नदियों के एकशन प्लान पर हज़ारों करोड़ का बजट कैसे डकारा जायेगा ? राजीव गांधी के जमाने से चले आ रहे इस नाटक का नया संस्करण मोदी सरकार ने अलग से उमा भारती के नेतृत्व में गंगा सफ़ाई मंत्रालय बना कर शुरू किया है। औद्योगिक इकाइयां बदस्तूर गंगा को दूषित कर रही है और सरकारी खजाना भी गंगा की सफ़ाई के नाम पर लुटाया जा रहा है।

देश की जनता का अरबों-खरबों रुपया डकारने का सिलसिला बनाये रखने के लिये प्रदूषण का स्तर लगातार बढते रहना बहुत जरूरी है। गत पचासों बरस से देश की तमाम सरकारें इस प्रयास में पूरी ईमानदारी से जुटी हुई हैं। यदि वे इस घृणित उद्देश्य के प्रति थोड़ी सी भी बेईमानी दिखातीं तो प्रदूषण इस कदर न बढता। यदि इन्हें प्रदूषण को बढने से रोकना होता तो सार्वजनिक परिवहन खासकर रेलवे नेटवर्क को मजबूत करते, वह भी इसके पूर्ण विद्युतीकरण के साथ। दूर जाने की जरूरत नहीं पलवल-फ़रीदाबाद-दिल्ली रेलमार्ग की ही हालत देख ली जाय। करीब 40 वर्षों से दिल्ली की रिंग रोड के समानांतर रिंग रेलवे लाइन पूरी तरह से ठप कर रखी है जिस पर सैंकड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ था। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रकों से माल ढोया जाता है, जो कि बहुत महंगा होने के साथ-साथ प्रदूषण बढाता है। यह सब इसलिये कि पर्याप्त रेल नेटवर्क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रेलवे घाटे में है। घाटे में क्यों है क्योंकि नीचे से ऊपर तक सारे चोर बैठे हैं जिनकी सरदारी रेल मन्त्री व प्रधानमंत्री करते हैं।

प्रदूषण से दिल्ली को बचाने के लिये 50 वर्ष पहले राजधानी की आबादी को नियन्त्रित करने के लिये एन सी आर बोर्ड का गठन किया गया था। इस बोर्ड ने एन सी आर का दायरा तो नारनौन, भिवानी, करनाल, अलवर, मथुरा व मेरठ तक बढा दिया लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया कि लोग दिल्ली में आने की बजाय एन सी आर के इन शहरों में ही अपनी जरूरतें पूरी कर ले जायें। विकास के नाम पर सड़कों के ऊपर सड़क, पुलों के ऊपर पुल बना कर दिल्ली में खरबों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। यदि यही पैसा एन सी आर क्षेत्र में खर्च किया गया होता तो लोग दिल्ली में आते ही क्यों और क्यों बढता वहां प्रदूषण ?

ख़बर दार

यदा-यदा हि धर्मस्य...

गीता में भगवान कृष्ण ने वायदा किया था कि जब-जब इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) में धर्म की हानि होगी, वे पृथ्वी पर अवतरित होंगे। लगता है भगवान को आलस्य ने घेर लिया है या वे विश्राम के मूड में हैं। लिहाज़ा उन्होंने महाभारत की जंग से छांट कर एक ऐसे किरदार को अपनी जगह भेजा है जिसने उस महायुद्ध में ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह किरदार है महाराजा शिखंडी का, जिनकी आड़ लेकर अर्जुन ने अक्षौहिणी कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह को मार गिराया था और पांडवों की विजय सुनिश्चित की थी। उसी शिखंडी के अवतार को आज दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के रूप में देखा जा सकता है। जंग की आड़ लेकर मोदी-राजनाथ के तीर उस केजरीवाल पर चल रहे हैं जो मतदाताओं के अपार बहुमत का नेतृत्व करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं। जंग से काल्पनिक साक्षात्कार।

म.मो.-आपको पुरखों से 'जंग' विरासत में मिला है। फ़िर भी आप शिखंडी के अवतार में ? बात समझ में नहीं आई ?

जंग-आप मीडिया वाले भी शिखंडी का महत्व नहीं समझते। क्या आपको नहीं पता कि शिखंडी ने ही भीष्म को मार गिराया था।

म.मो.-और जरा यह भी बता दीजिये कि शिखंडी के पीछे खड़े हो कर गांडीव से वार करने वाला धनुर्धर कौन था ?

जंग-अरे भाई वह तो अर्जुन ही था। शिखंडी को उसका दोष तो नहीं दिया जा सकता कि उसके पीछे कौन खड़ा हो कर क्या कर रहा था।

म.मो.-इसका मतलब आप से जो केजरीवाल पर वार कराये जा रहे हैं, उसके लिये आप दोषी नहीं हुए बल्कि आपके पीछे खड़े मोदी-राजनाथ हुए ?

जंग-भई मैं तो केन्द्र सरकार का नौकर हूं। मुझे उनके आदेशों की पालना करनी पड़ती है। केजरीवाल को जो तकलीफ़ हो रही है वह मोदी राजनाथ के आदेशों से, न कि मेरे आदेशों से।

म.मो.-यही तो महाभारत में भी हुआ था। वहां भी शिखंडी ने सिर्फ़ आड़ देने के पाखंड में अपनी भूमिका निभाई थी। वही काम आपको सामने रख कर किया जा रहा है।

जंग-क्या करें, केजरीवाल को भी तो भीष्म की तरह अपने हथियार त्याग देने चाहिये थे। पर यह कमबख्त युद्ध भूमि में डटा ही खड़ा है। जब मैं शिखंडी की भूमिका इतनी अच्छी तरह निभा सकता हूं तो यह भीष्म की भूमिका क्यों नहीं निभाता ?

म.मो.-आप एक आईएएस अफ़सर और वाइचांस्लर रहे हैं। आपके पास पैसे और मान-सम्मान की कोई कमी नहीं। फ़िर आपको शिखंडीपने की जलालत में पड़ने की क्या सूझी ?

जंग-शिखंडी को कोई आज तक भुला सका है क्या ? जंग को भी हमेशा याद रखा जायेगा।

रावण को मिल गयी एक नई सीता

सर्वविदित है कि भ्रष्टाचार रूपी रावण ने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। इसके 'पराक्रम' के आगे अच्छे-अच्छे वीर नतमस्तक हो रहे हैं। क्या कांग्रेसी, क्या भाजपायी, क्या सपाई, क्या बसपाई, ममता- जयललिता-बादल आदि समेत। बीच-बीच में किसी 'राम' के आने का ढिंढोरा भी पिटता है, जैसे 2014 में नरेन्द्र मोदी का पीटा गया था। पर इनकी पोल जल्दी ही खुल जाती है और रावण दनदनाता तीनों लोक में विचरण करता रहता है।

भला रावण हो और सीता न हो तो रामायण कैसे पूरी होगी ? कांग्रेस (यूपीए के 10 साला राज के दौरान मनमोहन सिंह सीता बने हुए थे। उनके तमाम मन्त्रियों, अफ़सरों, सहयोगियों और पार्टी वालों को भ्रष्टाचार के रावण ने अपने वश में कर लिया था। तो भी, कांग्रेसियों की ओर से यही तर्क दिया जाता था कि भ्रष्टाचार की क्या मजाल जो वह मनमोहन सिंह को छू सके। दूसरे शब्दों में मनमोहन सिंह भी सीता जैसी भूमिका में ही थे। उनकी सरकार को भ्रष्टाचार ने पूरी तरह अगवा कर लिया था पर वह भला मनमोहन सिंह को स्पर्श कैसे कर सकता था ?

मनमोहन सिंह तो खैर राजनीति के नैपथ्य में चले गये हैं। भ्रष्टाचार के रावण को मोदी राज में भी पहले की तरह ही दनदनाने की छूट मिली हुई है। पर उसे एक अदद सीता भी चाहिये थी। यह कसर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पूरी कर दी। क्रिकेट घोटाला में आकंठ डूबे जेटली के पक्ष में भाजपाई तर्क भी वही पुराना मनमोहन सिंह वाला ही है-भला जेटली को भ्रष्टाचार कैसे छू सकता है ?

लगता है रावण और सीता की यह रामायण यूं ही चलती रहेगी। क्योंकि 'राम' की इसे खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं लगती।